अनुदान संख्या 66 - चुनाव आयोग
GRANT No. 66 - ELECTION COMMISSION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	312,00,00				
				385,67,00	366,33,95	-19,33,05
पूरक	Supplementary	73,67,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					19,09,36
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	28,00,00				
				80,37,00	72,75,74	-7,61,26
पूरक	Supplementary	52,37,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7,60,53

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹1933.05 लाख) दिसंबर, 2023 तक प्राप्त पूरक अनुदान ₹7367.00 लाख का 26 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत रहीं।

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹1933.05 lakhs) constituted 26 percent of the supplementary grants of ₹7367.00 lakhs obtained December, 2023 and 5 percent of the total sanctioned provision.

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
चुनाव	Elections				
मू.	O.	31200.00			
पू.	S.	7367.00	36657.64	36633.95	-23.69
पु.	R.	-1909.36			

(I) निम्नलिखित शीर्षों के तहत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः—

(का) "प्रशिक्षण — चुनाव हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना" — ₹1360.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1130.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2490.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, आईआईआईडीईएम भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल के प्रस्तावित विकास का कार्यान्वयन न होने के कारण ₹351.51 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "निर्वाचन आयोग" —

(क) "स्थापना" — ₹22335.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4507.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹26842.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, आईटी अनुप्रयोगों के रखरखाव के लिए सेवा पेशेवर को काम पर न रखने और आयोग भवन के नियोजित नवीकरण का निष्पादन न होने के कारण ₹976.93 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "मतदाता जागरूकता" — ₹7500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1730.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹9230.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, नियोजित विज्ञापन कार्य के गैर—निष्पादन और कम पुस्तकों/पत्रिकाओं/जर्नल की छपाई के कारण ₹601.02 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुएः—

(I) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) "Training - Imparting training for Election" - the original provision of ₹1360.00 lakhs was augmented to ₹2490.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1130.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹351.51 lakhs - due to non-materialisation of proposed development of conference Hall at IIIDEM building.

(B) "Election Commission"-

(a) "Establishment"- the original provision of ₹22335.00 lakhs was augmented to ₹26842.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4507.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹976.93 lakhs - due to non-hiring of service professional towards maintenance of IT applications and non-execution of planned renovation of Commission Building.

(b) "Voter Awareness"- the original provision of ₹7500.00 lakhs was augmented to ₹9230.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1730.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹601.02 lakhs - due to non-execution of planned advertising work and printing of less books/magazines/ journals.

2. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"				
पूंजीगत परिव्यय अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	2100.00	1405.96	1405.96	...
पु.	R.	- 694.04			

(I) "निर्वाचन आयोग" के अंतर्गत – ₹694.04 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम आईटी उपकरणों की खरीद के कारण हुई।

(I) Under "Election Commission" - saving of ₹694.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to procurement of less IT equipment.